Yes, all of you men are laughing. I notice that. None of you ever have a child. Have you? (*Interruptions*) I am sorry unless you are given a certificate by the mother that you are the father of the child, you would also worry. So, it is with the right as a mother that I am requesting the Government to please re-examine the priorities. If it is right for us even to allow a child to work...

MR. CHAIRMAN: Put your question, please. Everybody accepts that all these males cannot become mothers.

SHRIMATI RENUKA CHOWDHURY: Please. I mean it in absolute sincerity. It is not right for children to work hazardous or non-hazardous. Children cannot grow in an environment which is not condusive to childhood. So, please consider this. The right to work should go to adult people who have the physical ability to work. So, let us see that child labour is abolished in totality.

श्री राम विलास पासवान: महोदय, इसीलिए मैं कह रहा था कि मैं अभी यह कहने की स्थिति में नहीं हूं। मैंने गरीबी को देखा है और मैं जब गरीबों की बात कहता हूं तो दिल से कहता हूं। यह मैं केवल जुबान से नहीं कहता हूं। बहुत से लोग रोड पर चलते चले जाते हैं और उनके सामने भीख मांगने वाला बच्चा जब कटोरा लेकर आता है तो शायद वे यह समझ नहीं पाते कि यह बच्चा कौन है, इसके मां-बाप कौन हैं। इनके लिये अभी तक, इन 42 सालों में क्या योजना बनी है ? इसीलिये मैंने कहा कि मैं इसको बहुत सिसरियेटी के साथ ले रहा हूं। जहां तक पालिसी और बिल का सवाल है, मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि हमारी सरकार पूरी पोलिटिकल विल के साथ जहां मजदूरों, गरीबों और दलितों की समस्याओं को साल्व करना चाहती है वहीं चाइल्ड लेबर ऐक्ट, हमारे पास जब साधन हो जायेंगे, तो तब इन्होंने जो बात कही है कि अबोलिशन होना चाहिये चाइल्ड लेबर का, कोई बच्चा काम नहीं करेगा, उसको खत्म किया जायेगा। लेकिन साधन कब तक होगा यह सत्ता पक्ष के लोग और विपक्ष के लोग सभी जानते हैं। इसलिये मैं माननीय सदस्या को यह जरूर बतलाना चाहूंगा कि बाल श्रमिकों के बारे में जो कानून बनायेंगे उनका हम कड़ाई से पालन करवायेंगे। हमने 21 तारीख को लेबर मिनिस्टर्स की कान्फ्रेन्स बुलाई है। उसके पहले यदि हमको आवश्यकता हुई और बाद में आवश्यकता हुई तो बाल श्रमिकों पर एक राष्ट्रीय सेमिनार भी करेंगे जिसमें सभी तपके के समाज सेवी संस्थाओं के लोगों को हम बुलायेंगे और इसमें जो आम सहमति होगी उसके आधार पर सरकार नीति बनायेगी।

नेहरू रोजगार योजना के लिए नए दिशा-निर्देश

*262. **श्री राम नरेश यादव* :**
श्री पशुपति नाथ सुकुल :

क्या **शहरी विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने "नेहरू रोजगार योजना" को जारी रखने का निर्णय किया है ;

(ख) यदि हां, तो इसके कार्यान्वयन में कितनी प्रगति हुई है ;

(ग) यदि उपर्युक्त भाग (क) का उत्तर "ना" हो, तो उसके क्या कारण हैं और क्या सरकार ने नेहरू रोजगार योजना को जारी रखने के लिए कोई नए दिशानिर्देश जारी किए हैं ; और

(घ) यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है ?

शहरी विकास मंत्री (श्री कुरान्नोली मारन) : (क) से (ग) एक विवरण सभा पटल पर रखा है।

---

*सभा में यह प्रश्न श्री राम नरेश यादव द्वारा पूछा गया।

विवरण

सरकार ने नेहरू रोजगार योजना को नया रूप दिया है तथा इसे जारी रखने का निर्णय लिया है। 1989–90 के दौरान केन्द्रीय सरकार ने अर्बन माइक्रो इन्टरप्राईजेज शहरी मजदूरी रोजगार तथा प्रशासनिक और प्रचालन खर्चों के लिए शहरी स्थानीय निकायों के क्षेत्राधिकर में योजना के कार्यान्वयन के लिए नेहरू रोजगार योजना निधियों के अपने अंश के रूप में राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को 117.15 करोड़ रुपये रिलीज किए हैं। इसके अतिरिक्त केन्द्रीय सरकार द्वारा आवास और आश्रय उन्नयन योजना के लिए अपने अंश के रूप में हुडको को 28.50 करोड़ रुपये की राशि रिलीज की गई है। इस कार्यक्रम के लिए केन्द्र सरकार के अंश के रूप में 1990–91 के केन्द्रीय बजट में 120 करोड़ रुपये की राशि का प्रावधान किया है। राज्य सरकारों के साथ विस्तृत विचार-विमर्शों के आधार पर सुधार के लिए कई बहु-मूल्य सुझाव प्रस्तुत किए गए हैं। इसके आधार पर इस योजना को नया रूप दिया गया है और संशोधित मार्ग-निर्देशन जारी किए गए हैं। संशोधित मार्ग-निर्देशनों में अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित प्रावधान किया गया है :—

(1) नेहरू रोजगार योजना के लिए केन्द्रीय अंश की निधियों विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को नियतित की जायेगी और राज्य सरकारें अर्बन माइक्रो इन्टरप्राइजेज तथा शहरी मजदूरी रोजगार योजनाओं के लिए राज्य स्तर, जिला स्तर, इन योजनाओं को कार्यान्वित करने वाले स्थानीय निकाय अथवा अन्य अभिकरणों के लिए केन्द्रीय सेरकार से प्राप्त निधियों को नियतित करने के लिए अनुज्ञेय होगी।

(2) माइक्रो इन्टरप्राइजेज एवं मजदूरी रोजगार की योजनाओं को कार्यान्वित करने के लिए उपयुक्त संगठनात्मक प्रबन्धों जैसे राज्य-स्तर अभिकरणों, जिला शहरी विकास अभिकरणों, स्थानीय प्राधिकरणों आदि का निर्धारण करने में राज्य सरकारें पूर्णतः स्वतंत्र होंगी।

(3) अर्बन माइक्रो इन्टरप्राइजेज की योजना के अन्तर्गत प्रशिक्षण पर विशेष ध्यान दिया जायेगा। यह प्रशिक्षण प्रदर्शन और कौशल उन्नयनोन्मुख होना चाहिए। प्रशिक्षण के लिए सम्पूर्ण मानदण्डों के अन्तर्गत प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों की संरचना और अवधि के बारे में पूर्ण स्वतंत्रता दी जाएगी।

(4) पहाड़ी राज्यों में विशेष स्थितियों को देखते हुए उन्हें एक लाख से कम आबादी वाली शहरी बस्तियों में भी आवास और आश्रय उन्नयन की योजना का प्रचालन करने के लिए अनुमति होगी। इसके अतिरिक्त राज्य सरकारों के अनुरोध पर इस योजना की विषयवार विषय आधार पर नये विकासशील औद्योगिक कस्बों पर लागू किया जा सकता है।

(5) उचित लाभग्राही की पहचान करने के लिए सर्वेक्षण किए जायेंगे और निष्कपटता तथा सम्भावित त्रुटियों के सुधार को सुनिश्चित करने के लिए सूचियां स्पष्ट रूप से प्रदर्शित की जायेंगी।

श्री राम नरेश यादव : महोदय, पिछली सरकार ने जवाहर रोजगार योजना गांव के विकास के लिये और विशेषरूप से जो गरीबी की रेखा के नीचे लोग रहते थे उनके लिये चलाने का काम किया था। इस कड़ी में इस बात को भी महसूस किया गया कि जो नगर हैं, हमारे टाउन एरियाज और कस्बे हैं, उनमें भी जो गरीबी की रेखा के नीचे लोग रहते हैं, जिनके लिये आवास की व्यवस्था नहीं हो पाती जिनके हाथों को काम नहीं मिलता है, विकास की रेखा जहां तक नहीं पहुंचती है, उसको ध्यान में रखकर और विकेन्द्रीकरण की स्थिति को भी ध्यान में रखते हुए तथा पिछले दिनों बलवंत मेहता कमेटी की रिपोर्ट आई थी, अशोक मेहता कमेटी की रिपोर्ट थी, श्री जयप्रकाश नारायण जी की भी रिपोर्ट थी, संसद सदस्यों की एक समिति ने भी इसे संशोधत करने की

बात की थी, इसको ध्यान में रखते हुए श्री राजीव गांधी के नेतृत्व में नेहरू रोजगार योजना पिछले वर्ष लागू की गई थी। उसमें इस बात का ध्यान रखा गया था कि कैसे कैसे, किस तरीके से किया जाए, आवास की व्यवस्था की जाए। केन्द्रीय सरकार ने इस बात की व्यवस्था की थी जो पैसा दिया जाएगा उसका 80 फीसदी केन्द्रीय सरकार वहन करेगी और बाकी 20 फीसदी राज्य सरकारें वहन करेंगी। इसलिए मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि आखिर जो गाइडलाइंस उस समय थी जो उस समय की सरकार ने दिशा-निर्देश दिये थे, उनको ध्यान में रखते हुए कौन सी ऐसी स्थिति बीच में आई कि जिसके आधार पर उन गाइडलाइंस में संशोधन करने की आवश्यकता पड़ी ? क्या कमजोरियां थीं क्या कमियां दिखाई दीं जिसके आधार पर गाइडलाइन्स को बदलने की आवश्यकता पड़ी यह मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं।

SHRI MURASOLI MARAN: Sir, we were compelled to recast the scheme because of certain valid reasons. Sir, we have nothing against the objectives of the NRY which are laudable. We have nothing against the components of the NRY. But regarding the modalities we encountered certain difficulties. Even at the first instance, certain States like Andhra Pradesh, West Bengal and Tamil Nadu have objected to the fact that funds should not be routed through the District Magistrates. They all wanted that the funds should be routed through the State Governments and practically we also saw that routing the funds through the District Magistrates or the District Rural Development Agencies did not pay dividends. So in order to arrive at a workable arrangement, we have changed the guidelines. Now, instead of the District Magistrates, the money will be allocated to the State Government. Now greater flexibility is given to the State Governments and Union Territories in the allocation of funds. They in turn, if they want, can allocate the funds to the Municipalities. Some of the State Governments have expressed an opinion that it would be better to create a new organisation or agency in the name of District Urban Development Agencies on the model of District Rural Development Agencies. So we have said 'yes', States now can have flexibility; enther they can send the money to the Municipalities or to the new proposed agencies like District Urban Development agencies. So these are the major changes. At the same time, regarding identification of the beneficiaries also we have given more flexibility to the State Governments. We also asked them that it should be publicised and there should be statistics taken about the urban poor and then only selection should be made and it should be publicised and objections should be called for and if necessary the list should be finalised thereafter only. So these are the changes made in the scheme to make it more effective and more functional.

श्री राम नरेश यादव : सभापति महोदय, जो विकेन्द्रीयकरण की सब से अच्छी और मीढिया नीति थी कि जिले तक, टाउन एरिया तक और म्युनिसिपल बोर्ड तक पहुंचाएं उसको आपने ला कर फिर प्रान्त में रख दिया। इसलिए योजना की व्यवस्था वहां के लोग आसानी से कर सकते थे। उस में निश्चित रूप से टाउन एरिया, म्युनिसिपिल बोर्ड और एक लाख की आबादी के नीचे जहां की जनसंख्या है वहां के लोग अपने लिये योजना बना सकते थे जिसके आधार पर सारा काम किया जाना था लेकिन वहां से हटा कर आपने स्टेट में ला कर के खड़ा कर दिया हैं, इससे विकेन्द्रीकरण की दिशा में कठिनाई पैदा हो गई । दूसरी बात मैं यह जानना चाहता हूं कि सरकार जब इतनी सजग है, चाहती है कि इस काम को तेजी के साथ किया जाए तो पिछले वर्ष 150 करोड़ रुपया केन्द्रीय सरकार ने रखा था और इस साल आपने आ कर उसमें उसका 90 प्रतिशत यानी 120 करोड़ रुपया रखा हैं।

मान्यवर, मैं जानना चाहता हूं कि इतनी बड़ी आबादी वाला जो क्षेत्र है उन क्षेत्रों के लिए जहां पिछली सरकार ने 150 करोड़ रुपये की योजना रखी थी

क्या वजह है कि आप जब इसकी महत्ता को भी स्वीकार करते हैं, दूसरी चीजों को भी स्वीकार करते हैं तो 30 करोड़ घटाकर 120 करोड़ रखे हैं और आज की महंगाई में जबकि इन्फ्लेशन भी बढ़ गया है। इसको ध्यान में रखते हुए 120 करोड़ रुपये रखने का क्या औचित्य है यह माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं क्योंकि यह सरकार लगता है, कहती कुछ है, करती कुछ है। इसलिए जिधर ध्यान देना चाहिए उधर ध्यान न देकर दूसरी चीजों की तरफ ध्यान दे रही है। क्या कारण है कि ऐसे लोगों के लिए जो गरीबी रेखा के नीचे रहते हैं, कोंपड़ियों में रहते हैं, कस्बों में रहते हैं जिनको रहने के साधन नहीं है जिनकी व्यवस्था होनी चाहिए। फिर क्या वजह है कि इस बार आपने घटाकर 120 करोड़ रुपये रखने का काम किया है। यह मैं समझता हूं कि ऐसे लोगों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ करने के अलावा और कुछ नहीं है।

SHRI MURASOLI MARAN: Sir, I am thankful to the hon. Member for having given me an opportunity to explain this situation. Sir, according to him, in the last year's Budget, Rs. 150 crores had been allocated and this year the amount is only Rs. 120 crores. He is perfectly right. But it needs some clarification. What happened last year was the NRY did not take off at all. It was grounded. For example, the previous Prime Minister announced the scheme on 11th October 1989 and by 8th to 11th November 1989, about Rs. 40 crores were sent to all the DMs and the DMs deposited the money in the scheduled Banks. At that time, the understanding given to all of us was, the Reserve Bank will charge a rate of interest of only 10 per cent like it charges for the IRDP and other social welfare schemes but suddenly, by the middle of December, we got another directive saying that, no, we will not charge 10 per cent; we will charge 15.5 per cent. Sir, Rs. 40 crores are lying without being used, without getting the equivalent amount from some States and the financial institutions. Moreover, another Rs. 60 crores worth of funds have also been lying with the banks since Novecber with regard to the Urban Wage Employment Scheme out of which hardly Rs. 5 crores or Rs. 10 crores has been spent so far. (*Interruptions*). This money is earning interest like savings bank account—just about 5 per cent. We have been pleading with the Reserve Bank that the rate of interest should be reduced. They are considering a rate of interest of 10 per cent. The negotiations are going on. But what I am telling is, probably within a day or two or within a week, we may get a favourable reply from the Reserve Bank. This year, Rs. 120 crores have been allocated. Rs. 40 crores are already lying there. So, Rs. 40 crores plus Rs. 120 crores, it comes to Rs. 160 crores. There is no question of reduction on this account.

श्री राम नरेश यादव : मान्यवर, जब मालूम है कि इतने करोड़ रुपया रखा गया है, तो यह आपकी जिम्मेदारी थी। उस सरकार के चले जाने के बाद क्यों नहीं यूटिलाइज किया गया और उस रकम को लेकर यहां पर जोड़ने की कोई जरूरत दिखाई नहीं देती।

SHRI P. N. SUKUL: Mr. Chairman, Sir, the revised guidelines have obviously been made to please the State Governments. The Congress Government routed the money through the District Magistrates and although it had its own State Governments in many States, it did not oblige those State Governments and in the best interests of the people, it routed the money through the DMs and others. (*Interruptions*). Now, as the Minister has just said and as is mentioned here in the statement, the State Governments are being granted greater flexibility in emplementing the Nehru Rajgar Yojana. It has ben said that the State Governments will have flexibility in allocating funds received from the Central Government and the State Governments will have full flexibility in determining the appropriate organisational arrangements also. In this connection, I would like to know whether the Central funds for the NRY are to be allocated to the States on the basis of their demands based upon any schemes made by them under urban micro enter-

prises and urban wage employment or, the allocation is to be made by the Centre on an *ad hoc* basis.

Secondly, how much money is proposed to be allocated to the different States for the NRY in 1990-91?

Thirdly, how many urban youth have so far been benefited by the NRY?

SHRI MURASOLI MARAN: Sir, I will answer his last question first. The hon. Member wanted to know how many youth have been given jobs under this scheme. I am very sorry to say that this noble scheme did not take off because of the difficulties in regard to interest rates, on account of elections, etc. Now, we are geared to take off and, this year, according to the original assumption, we can give jobs to one million youth in the urban areas.

Secondly, the hon. Member made an accusation that just to please the States, we have made this change. It is not so. Some of the States made a complaint that they could not monitor the programme. That is why when we asked for details...

SHRI JAGESH DESAI: You name the States. (*Interruptions*)

SHRI MURASOLI MARAN: They complained that they could not monitor the scheme. Moreover, it is a question of ideology. The National Front went to the people on this solemn question that we stand for democratic federalism. Therefore, we do not want to erode into the autonomy of the States. That is why we have made this change.

SHRI V. NARAYANASAMY: It is not a political platform.

SHRI P. N. SUKUL: How are the funds to be allocated? On the basis of the demands of the States or on an *ad hoc* basis?

SHRI MURASOLI MARAN: We go by the norms set by the previous Government. We take into account the number of urban poor and, accordingly, allocation will be made; not on the basis of their demands.

श्री राम चन्द्र विकल: सभापति जी, माननीय मंत्री जी ने अभी बताया कि 120 करोड़ इस बजट में इस सरकार ने रखा और 40 करोड़ रुपया बैंकों में अलग से जमा है। मैं जानना चाहता हूं कि केन्द्रीय सरकार अपने द्वारा किस-किस योजना में इसको लगाना चाहती है, और राज्य सरकारों से भी इस योजना के कार्यान्वियन के लिए अगर कोई बातचीत हुई है, तो उसका ढांचा आपके पास क्या है? हर राज्य को अलग-अलग विस्तार योजनाओं का नाम बताने की कृपा करें।

SHRI MURASOLI MARAN: There are several schemes. For example, regarding upgradation of dwellings, the HUDCO is in touch with the local agencies like the Slum Clearance Board, Housing Board, etc., for their own schemes. For employment through housing the shelterless urban population between one lakh and twenty lakhs, there is this scheme. For wage employment through creation of socially useful public assets, there are several schemes. There is no dearth of schemes.

SHRI S. B. CHAVAN: Sir, I can well appreciate the flexibility which has been introduced in the NRY. Does it mean that each State Government will have the authority to alter the scheme according to their own way of thinking?

There has been a practice of giving block grants to the State Governments and the normal experience is that it does not reach the targeted groups. These amounts are not being properly utilised. The only point which the Government will have to consider will be, how to ensure that the amount which has been given by the Central Government for the NRY is not utilised for any other purpose. That is one thing. And another is that Rs. 40 crores were lying in the banks and we are still in correspondence with the Reserve Bank to fix the rate of interest. I do not think that the Finance

Ministry or for that matter, even the Administrative Ministry also, should agree to keep this amount in a bank. I don't think that you have moderate or adequate resources at your disposal that you can afford to keep the money in the banks on interest and thereby blocking the money in the bank. That will be a totally wrong kind of approach and the steep magnitude of the problem of unemployment is of such a huge order that to say Rs. 40 crores were lying there and that is why we have reduced from 150 to 130 or 120 crores... (*Interruptions*)...

SHRI VIRENDRA VERMA: What is the question?

SHRI S. B. CHAVAN: I cannot possibly help you if you don't understand the meaning of what I am saying. Sir, my question is this. Is it still under contemPlation that district urban Development Corporations are going to be set up by the State Government? And till then, is this kind of flexibility going to continue? After these corporations are created, the State Government will not have any kind of flexibility. That is my point, Sir.

SHRI MURASOLI MARAN: Sir, I have great respect for the hon. Member who is a former Chief Minister and a former Finance Minister of the country. Sir, such problems arise in all Centrally sponsored schemes. So similar problems also may be encountered in this case. Regarding the flexibility, some States wanted to create an organisation like this. So the flexibility in this context means that if they want to have an organisation, let them have it. If they want the money to be sent to those organisation, it can be so sent. This is the arrangement. It is for the State Governments to decide how the money should be sent and to whom the money should be sent. Regarding the programme that he has mentioned, we will take adequate precaution to see that the money reaches the target grop. For example, HUDCO is there. Regarding upgradation of shelter and the municipalities and others, if they are to do it, they have to do it with much publicity under the public gaze. And the public criticism will be there if they divert the money.

MR. CHAIRMAN: Prof. Thakur.

PROF. CHANDRESH P. THAKUR: The Problem of urban unemployment is not only very serious but it is also explosive. Now when the Minister was making a reply to the earlier supplementary, he almost made a political speech.

MR. CHAIRMAN: Don't make another political speech but come to the point.

PROF. CHANDRESH P. THAKUR: I need your protection.

MR. CHAIRMAN: You put a question, please.

PROF. CHANDRESH P. THAKUR: We, in the Rajya Sabha, represent the States and no Member of this House can be and has ever been a party to the weakening of the authority of States. Let this go on record. So to the extent that the Minister alluded to the possibility that there is an intention to weaken the autharity of the States, I think, he has been misled by whoever has advised him like this.

MR. CHAIRMAN: What is your question?

PROF. CHANDRESH P. THAKUR: Sir, the question is this. While we are trying to politicise the issue between the Centre and the States or the disrict level authority, the Congress programme or the non-Congress programme, the Nehru Rozgar Yojna or something else, the real fact is... (*Interruptions*)

MR. CHAIRMAN: Have you put the question? You don't. Please put a question.

PROF. CHANDRESH P. THAKUR: Is there any guarantee that in the revised schemes that the resources allocated for urban unemployment will be used for the purposes for which they are guaranteed; that under no circumstances, the

resources allocated for one district will be diverted to the other district; and that the State Government will release the allocated funds within a time-bound programme, rather than procrastinating on it and seeing that the amount remains unspent and has been put in a bank to earn some interest?

SHRI MURASOLI MARAN: Sir, the in-built protections are there in the guidelines.

MR. CHAIRMAN: Question No. 263.

Assignment of fertiliser project to M|s. Snam Progetti

*263. DR. BAPU KALDATE: Will the Minister of AGRICULTURE be pleased to state:

(a) whether it is a fact that M|s. Snam Progetti of Italy was assigned under a deal to set up units of Phulpur Fertiliser Project in Uttar Pradesh;

(b) whether it was also assigned fertiliser contract at Trombay during 1974-75;

(c) whether it is also a fact that M|s Gujarat Narmada Valley Fertiliser Company (GNFC) was asked to cancel its contract with M|s. Toyo of Japan and then it was assigned to M|s. Snam Progetti of Italy;

(d) if so, what are the details of the total assignments of M|s. Snam Progetti in the country under the project with the Ministry; and

(e) the name and the locations of each project alongwith the progress made so far in each case?

THE DEPUTY PRIME MINISTER AND THE MINISTER OF AGRICULTURE (SHRI DEVI LAL): (a) Yes, sir M/s. Snam Progetti were given the contract for engineering consultancy of the urea plant of Phulpur based on international competitive bidding.

(b) Yes, Sir for Ammonia and Urea plants of Trombay-V in December 1976.

(c) M|s. Gujarat State Fertiliser Company as the promoters of M|s. Gujarat Narmada Valley Fertiliser Company entered into a contract with M/s. Snam Progetti for the urea plant in Sept., 1976. Since a contract had not been signed with M/s. Toyo Engg. Corporation of Japan the question of its cancellation did not arise.

(d) and (e) The details of scope of work assigned to M|s Snam Progetti, the fees paid|payable as per contract and the status of the projects are given in the statement attached. [See Appendix CLIII. Annexure No. 88].

डा. बापू कालदाते : सभापति, जी, यह सारे प्रश्नों का विस्तारित उत्तर यहां प्राप्त हुआ, यह हमें अच्छी बात लगी । यह स्नेम प्रोगेत्ति और इस एसोसियेट के बारे में देश में काफी चर्चा चलती रही । अगर इसमें यह जुड़ा हुआ निवेदन पढेंगे तो इसका भी पता लगेगा कि देश में जितने –जितने फर्टिलाइजर्स के यूनिट है, इसमें इसी कंपनी को सहभाग सबसे ज्यादा गया है । यह ठीक है कि उन्होंने यह कहा है कि गुजरात जी० एन०एफ०सी० वाला कांट्रेक्ट नहीं दिया था, लेकिन क्या यह बात सही है कि जापान की टोयो कंपनी को लैटर आफ इण्टेण्ट भेजा गया था ? अगर यह लेटर आफ इण्टेण्ट भेजने के बाद दूसरे को कांट्रेक्ट दिया गया तो ऐसा क्यों हुआ ? यह मेरा पहला "अ" सवाल है। दूसरा "ब" सवाल यह है कि सरकार आज आत्मनिर्भरता की बात कर रही है, उसको ध्यान में रखते हुए हिंदुस्तान में जो कंसलटेन्सी एजेन्सी मौजूद है, उपलब्ध है, जो कई सालों से काम करती है, जैसे पी०डी०आई० एल०, एफ० जी० ओ० या फेक्ट है, इनको बढावा देकर बाहर की कंपनीयों के साथ रिश्ते कम करें और हम ज्यादा से ज्यादा आत्मनिर्भर होने की दिशा में प्रयास करें। इस दृष्टि से क्या सरकार फिर से इस बारे में सोचकर भारतीय कंपनियों को ज्यादा से ज्यादा बढ़ावा देने की दिशा में कदम उठा रही है ?